



2026:AHC:64099

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9394 सन् 2026

अमरनाथ चौबे

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के ओर से अधिवक्ता : चन्द्र शेखर सिंह, रघुबीर सिंह

विपक्षी के ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. श्री चन्द्र शेखर सिंह, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, तथा श्री शिवदत्त शुक्ला, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादीगण की ओर से, को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. प्रस्तुत जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत आवेदक अमरनाथ चौबे की ओर से अपराध संख्या 641 सन् 2025, उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 की धारा 3/5क/5ख/8 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 के अन्तर्गत, थाना अली नगर, जनपद चन्दौली में पंजीकृत मामले में, विचारण लम्बित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा इस मामले में उसे मिथ्या रूप से फँसाया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक उस वाहन का स्वामी बताया जाता है जिससे छः जीवित एवं चार मृत गायें बरामद बताई जाती हैं। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक दिनांक 06.02.2026 से जेल में निरुद्ध है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक ने वचन दिया है कि यदि

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत प्रदान की जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में वादों की अत्यधिक लम्बितता के कारण विचारण के शीघ्र समापन की कोई सम्भावना नहीं है।

4. इसके विपरीत विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

5. आवेदक उस वाहन का स्वामी बताया जाता है जिससे छः जीवित एवं चार मृत गायें बरामद बताई जाती हैं। आवेदक दिनांक 06.02.2026 से जेल में निरुद्ध है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. समस्त तथ्यों, प्रकृति एवं अभिलेख में परिलक्षित साक्ष्य की समग्रता पर विचार करने के उपरान्त तथा वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, मुझे यह एक जमानत के योग्य प्रकरण प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक **अमरनाथ चौबे**, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को रुपये 50,000/- (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत मुचलका एवं उसी धनराशि में दो प्रतिभूतियाँ सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय के समक्ष अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विरत हो जाये या साक्ष्य से छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा / उन्हें भयभीत नहीं करेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा, उन तारीखों पर जो (i) वाद का प्रारम्भ, (ii) आरोप-निर्धारण, एवं (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अन्तर्गत कथन अभिलिखित किये जाने के लिए नियत की गयी हों।

(iv) आवेदक यह वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि साक्ष्य की तारीखों पर, जब साक्षीगण विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, वह कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत निरस्त किये जाने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कहा गया कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण हेतु सीमित है और किसी भी प्रकार से वाद के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझी जाएगी। विचारण न्यायालय इस आदेश में कहे गये किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना, प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर पूर्णतः स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

26 मार्च, 2026

आशीष/-

(माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।